



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, १६ जनवरी, १९९६/२६ यौष, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, १६ जनवरी, १९९६

संख्या १-७/९६-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन (संशोधन)

विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 6) जो दिनांक 16 जनवरी, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा

1996 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1996 है। संक्षिप्त नाम।

1971 का 4 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उप-धारा (1) में "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "दो हजार" शब्द रखे जाएंगे। धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10-क में "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे। धारा 10-क का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जोकि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तज वृद्धि के कारण उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थापना या उसके स्थायी निवास स्थान पर संस्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय की प्रतिपूर्ति को एक हजार पांच सौ से दो हजार रुपये प्रति मास तक बढ़ाना और रेलवे या वायुमार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा की अधिकतम सीमा किसी वित्तीय वर्ष में चालीस हजार किलोमीटर से पचास हजार किलोमीटर तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। अतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह;
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
15 जनवरी, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित किए जाने पर, राजकोष से प्रति वर्ष 0.12 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या जी० ए० डी० सी० (पी० ए०) 4-24/94]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 1996.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S
AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT)
BILL, 1996**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 1996.

Short title.

4 of 1971

2. In section 8 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), in sub-section (1), in first proviso, for the words "one thousand and five hundred", the words "two thousand" shall be substituted.

Amendment
of section 8.

3. In section 10-A of the principal Act, for the words "forty thousand", wherever these occur, the words "fifty thousand" shall be substituted.

Amendment
of section
10-A.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Speaker and Deputy Speaker as a public representative, had to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase the reimbursement of telephone charges from Rs. 1500/- to 2000/- per month to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence and to raise the maximum limit of free transit by railway or by air facility from forty thousand kilometres to fifty thousand kilometres in a financial year. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives,

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 15th January, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer, to the tune of Rs. 0.12 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE
207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(PA)4-24/94]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 1996, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.